बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 150

सुस्त मांग का असर

अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ समय से मांग में आई अनदेखी सुस्ती के बीच कई विशेषज्ञ इसके कारण एवं समाधान बता रहे होंगे। इस चर्चा में यह भी छोटा सा योगदान है।

भारतीय उपभोक्ता कर्ज में आकंठ डूबे हुए हैं। कटौतियों के बाद हाथ में आने वाले वेतन का एक बड़ा हिस्सा कर्ज भुगतान की मासिक किस्त (ईएमआई) में चला जाता है क्योंकि उपभोग का एक बड़ा हिस्सा उधार की रकम से ही जोर पकड़ता है। इससे भी बुरी बात है कि कई लोग उन घरों या फ्लैटों के लिए उठाए कर्ज की भी किस्त भर रहे हैं जिनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

दूसरा, निम्न मुद्रास्फीति के प्रभावों पर सोचें। वेतन वृद्धि कम होती जा रही है लिहाजा समय के साथ किस्त के बोझ में मिलने वाली राहत नदारद हो चुकी है। ब्याज दरों के भी नीचे आ जाने से लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए अधिक बचत करने और फिलहाल कम खर्च करने को मजबूर हैं। तीसरा कारण नकारात्मक धन प्रभाव है। रियल एस्टेट की कीमतें 25 फीसदी से भी अधिक गिर चुकी हैं। शेयर बाजार सूचकांक भी एक साल पहले की तुलना में निचले स्तर पर हैं और कई म्युचुअल फंडों ने नकारात्मक नहीं तो खराब प्रतिफल दिया है। जब लोग खुद को गरीब महसूस करने लगते हैं तो वे कम खर्च करते हैं।

चौथा, श्रमशक्ति में पहले से कम महिलाएं होने से रोजगार ढांचा भी बदला है। महिलाओं के अधिक समय तक पढ़ने, कुलीनता का भाव आने, आते-जाते समय सुरक्षा की कमी और उपलब्ध कार्य न होने जैसे कारणों से एक औसत परिवार में कामकाजी वयस्कों की संख्या कम हो गई है। निश्चित रूप से इसका असर परिवार की आय पर होगा। पांचवां कारण लोगों के अधिक समय तक जीवित रहने से जुड़े प्रभाव हैं। साठ साल से अधिक उम्र वाली आबादी जनसंख्या की समग्र वृद्धि दर से करीब दोगुनी दर से बढ़ रही है। बुजुर्गों की देखभाल करने से परिवारों पर स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ बढ़ता है। आवास, वाहन, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों एवं शिक्षा को छोड़कर अन्य कारणों से लिए जाने वाले घरेलू कर्ज में तीव्र वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ हिस्सा निश्चित रूप से इलाज पर हुए खर्चों की भरपाई के लिए होगा।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

छठे कारण का उल्लेख रथिन रॉय अपने लेख में कर चुके हैं। उत्पादों एवं सेवाओं की मांग का बड़ा हिस्सा एक पतली ऊपरी परत से ढका हुआ है। हालांकि यह आवरण उतना पतला भी नहीं है क्योंकि कुल आबादी का 30-35 हिस्सा उपभोग करने वाले दस्ते में शामिल है। मसलन, 2011 की जनगणना बताती है कि 24.6 करोड़ में से 21 फीसदी परिवारों के पास दोपहिया वाहन थे। आज के समय में यह अनुपात अधिक ही होगा क्योंकि करीब छह फीसदी परिवार हर साल दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं। फिर भी रॉय इस मामले में सही हैं कि खर्च करने वाला तबका उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। एक कारण यह होगा कि श्रम-आधिक्य वाले विनिर्माण की वृद्धि निम्न-मध्य वर्ग के स्तर पर बड़ी व्यय श्रेणी बनाने में सफल नहीं हो पाई है। निम्न उत्पादकता और उसकी वजह से आय भी कम होने से 'गिग इकॉनमी' भी विकल्प नहीं रह गई है।

आखिर में, कृषि क्षेत्र में बदलाव का दौर है। किसान अब घरेलू बाजार की खपत से अधिक पैदावार करते हैं। लेकिन अधिक उपज का निर्यात नहीं हो पाने से घरेलू मांग एवं आपूर्ति के बदलते संतुलन ने कीमत संबंधी दबाव पैदा किए हैं जो कृषि आय को सीमित कर देता है। अगर श्रम अधिकता वाली विनिर्माण गतिविधियां सफल हुई रहतीं और लोग खेतों से निकलकर कारखानों में पहुंचे रहते तो खेती में लगे कम लोगों का ही पेट भरना पड़ता।

मजदूरी की सघनता वाले विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए श्रम सुधार, प्रतिस्पर्द्धी कीमत वाले रुपये, सक्षम ढांचागत आधार और आपूर्ति शृंखला विकास जैसे बदलावों की जरूरत है। कुछ मुद्दे सरकार के एजेंडे में हैं लेकिन कई श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिता बनाना ही काफी नहीं है। केवल कानूनों की संख्या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के दबाव में आकर सरकार तात्कालिक समाधानों का रुख कर सकती है। इसे समझा जा सकता है लेकिन किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। संरचनात्मक बदलावों के बगैर टिकाऊ आर्थिक वृद्धि का रुझान नीचे की तरफ ही बना रहेगा।

अजय मोहंती

जलवायु परिवर्तन पर कदम और उनकी भू-राजनीति

जलवायु के अनुकूल तकनीक पर नियंत्रण ही भविष्य में भू-राजनैतिक शक्ति का माध्यम बनेगा। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **नितिन देसाई**

जून और जुलाई 2019 दर्ज इतिहास के सबसे गर्म महीनों में शामिल रहे हैं और 2015 से 2019 तक का समय सबसे गर्म पांच वर्ष का समय रहा है। भारत में दिल्ली के पालम में 10 जून, 2019 को 48 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में तापमान बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर गया। यूरोप और अमेरिका में भी अप्रत्याशित गर्मी देखने को मिली।

विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के महासचिव पेटेरी टालास के मुताबिक अत्यधिक गर्मी के साथ-साथ ग्रीनलैंड, आर्कटिक और यूरोपीय ग्लेशियरों में जमकर बर्फ पिघली। आर्कटिक में लगातार दूसरे महीने जंगलों में आग लगी और वे घने जंगल नष्ट हो गए जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते थे और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करते थे। यह कोई विज्ञान गल्प नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की हकीकत है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हालात और खराब होंगे।

ये गर्म हवाएं केवल नमूना भर हैं। यदि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो हालात और खराब होंगे। बाढ़, सूखा, बारिश में कमी, तूफानों का आना, तटीय इलाकों के मीठे पानी में खारापन, कृषि एवं जैव उत्पादकता पर असर बढ़ेगा। कुलमिलाकर जलवायु से जुड़ी आपदाएं बढ़ेंगी और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। दुनिया का कोई देश अपने दम पर इससे निपट नहीं सकता क्योंकि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन समूची पृथ्वी पर असर डालने वाला है।

यही कारण है कौन क्या करता है और किसे क्या करने को मजबूर किया जाता है, इसकी भू-राजनीति अब जलवायु कूटनीति की चिंता के मूल में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2019 में जलवायु परिवर्तन पर बहस होने वाली है, उससे कुछ संकेत निकल सकते हैं।

नेचर पत्रिका के एक हालिया आलेख में जलवायु परिवर्तन की भू-राजनीति के चार संभावित परिदृश्यों पर चर्चा की गई है।

पहला परिदृश्य काफी हद तक अकल्पनीय है। इसमें विभिन्न देशों के बीच बोझ की साझेदारी के मामले में गहन सहयोग की बात की गई है। जीवाश्म ईंधन कंपनियों को वित्तीय बाजार के माध्यम से हाशिये पर करने, हरित तकनीक वाली कंपनियों के उभार और सभी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही गई है।

दूसरा परिदृश्य एक तकनीकी बदलाव की परिकल्पना करता है, जहां स्वच्छ ऊर्जा की आर्थिकी में नाटकीय बदलाव की बात कही गई है। इसका एक समतुल्य उदाहरण मोबाइल फोन तकनीक से लिया जा सकता है जिसने दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति ला दी। परंतु यह परिदृश्य कुछ देशों के बीच तकनीकी दबदबे और प्रतिद्वंद्विता की तस्वीर भी पेश करता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन आज ऐसे किसी कदम के बारे में पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

तीसरा परिदृश्य बढ़ते लोकलुभावन राष्ट्रवाद का एक जोखिम भरा चित्र प्रस्तुत करता है जहां उत्सर्जन में कमी के तमाम प्रयास ठप होने की बात है। चौथा परिदृश्य वह है जो हम अभी कर रहे हैं। यानी पेरिस जैसे कमजोर समझौते। इससे कुछ सहायता मिलेगी लेकिन हम ताप वृद्धि के तय लक्ष्यों से पीछे रह जाएंगे।

दुर्भाग्य की बात है कि लोकलुभावन राष्ट्रवाद के परिदृश्य से गुजर रहे है। ट्रंप प्रशासन पेरिस समझौते की आलोचना कर चुका है, यूरोप में क्षेत्रवाद बढ़ रहा है और वहां प्रवासियों को लेकर चिंता बढ़ रही है।

लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देश वैश्वीकरण को नकार चुके हैं। इनमें से कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारें हैं जो मानवजनित जलवायु परिवर्तन तक को स्वीकार नहीं करतीं। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन पर कदम उठाने को लेकर आम जन का प्रतिरोध बढ़ेगा क्योंकि ऐसी घटनाएं भी बढ़ेंगी।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 5 फीसदी जबकि चीन की 25 फीसदी है।

हालांकि 2030 तक दोनों की हिस्सेदारी 20-30 फीसदी रहेगी और उन पर कदम उठाने का जबरदस्त दबाव होगा। बहुराष्ट्रवाद के क्षरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह व्यापार, तकनीक हस्तांतरण या वैश्विक पूंजी बाजार की मदद से एकतरफा दबाव में तब्दील हो जाएगा। भारत और चीन को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और खुद को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदमों का अगुआ बनाना चाहिए।

कार्बन ऐक्शन ट्रैकर्स भारत की पेरिस प्रतिबद्धता को वैश्विक सहयोग की आवश्यकता के अनुरूप आंकता है। हालांकि वह चीन की प्रतिबद्धता को काफी कम मानता है। दोनों देश पेरिस प्रतिबद्धता की लीक पर हैं बल्कि वे वादे से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हालिया अध्ययन यह भी बताता है कि चीन का उत्सर्जन पेरिस समझौते में किए उल्लेख से एक दशक पहले ही उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है।

जहां तक बात है जलवायु से जुड़ी भू-राजनीति की तो दोनों बड़े देशों में काफी कुछ एक समान है। दोनों का हित इसी में है कि अतीत के उत्सर्जन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में दोनों देश मिलकर काम करें तो भविष्य के विकास के लिए मौजूदा कार्बन स्पेस में उचित दखल कायम करें। दोनों देशों में तेल की कमी है और सौर तथा पवन ऊर्जा को वे केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी के विकल्प के अलावा ऊर्जा सुरक्षा के उपाय के रूप में भी देखते हैं। दोनों देश कोयले पर काफी हद तक निर्भर हैं और कोयले का इस्तेमाल कम करने तथा नई तकनीक विकसित करने तथा अपनाने में दोनों के हित जुड़े हैं।

तथ्य यह है कि घरेलू विकास के लिए हमें प्रभावी जलवायु कार्य योजना की आवश्यकता है। कोयले पर निर्भरता के अलावा दोनों देश जलवायु के अनुकूल वृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में वास्तविक नेतृत्व तभी मिलेगा जब वे दूसरों से कुछ अलग कदम उठाएं। उन्हें जो गुंजाइश बनानी है या सार्वजनिक परिवहन, भवन डिजाइन, शहरी नियोजन, ऊर्जा किफायत वाले विनिर्माण आदि के क्षेत्र में जिस पैमाने पर जलवायु के अनुकूल तकनीक इस्तेमाल करनी है, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी।

ये दोनों देश यह काम करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनकी इमारतों, शहरी क्षेत्र, विनिर्माण क्षमता और बिजली संयंत्र आदि अभी बनने हैं। आवश्यकता केवल यह समझने की है कि जलवायु के अनुकूल तकनीक पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। जो देश ऐसा करने में कामयाब रहेगा वही भविष्य में भूराजनैतिक शक्ति का स्रोत बनेगा। चीन पहले ही इस राह पर बढ़ चुका है और भारत अगर जलवायु परिवर्तन की भूराजनीति में पिछड़ना नहीं चाहता तो उसे भी ऐसा करना होगा।

काफी कुछ सीखा जा सकता है भारत रत्न प्रणव मुखर्जी से

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने किसी तरह का समझौता किया। उन्हें यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने मिले हुए अवसरों का लाभ उठाया और इस दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं से कभी समझौता भी नहीं किया। इसमें कहीं न कहीं एक सबक छिपा हुआ है।

वह 22 मई, 2004 की एक गर्म शाम थी। उस दिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को शपथ लेनी थी। दिल्ली में कांग्रेस का गठबंधन राजनीति का यह पहला बड़ा प्रयास था। टेलीविजन चैनल यह अटकल लगाने में व्यस्त थे कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा? उस वक्त प्रणव मुखर्जी अपने तालकटोरा रोड स्थित घर के छोटे से अध्ययन कक्ष में बैठे थे और केंद्रीय गृह मंत्रालय के कामकाज से संबंधित विभिन्न रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गोपनीय ढंग से बता दिया था कि वह कुछ ही घंटों में देश के गृहमंत्री बनने वाले हैं। कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था और कुछ समाचार चैनल जो उन्हें गृहमंत्री मान भी चुके थे, उन्होंने इन हमलों पर मुखर्जी की टिप्पणी भी चला दी।

देर शाम जब चैनलों ने मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों के नाम जारी किए तो मुखर्जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था। तालकटोरा रोड स्थित उनके आवास पर किसी को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके करीबी सहयोगियों को यह गलतफहमी थी कि रक्षा मंत्री का पद गृह मंत्री से छोटा होता है और यही कारण है कि वे स्तब्ध और नाराज थे।

परंतु स्वयं मुखर्जी ने क्या किया? उन्होंने नए हालात को अपनाने में 10 से 15 सेकंड का वक्त लिया। वह शौचालय गए और वहां से वापस आकर उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया कि रक्षा सचिव से उनकी बात कराई जाए।

प्रणव मुखर्जी उस वक्त संप्रग के सबसे अनुभवी मंत्री थे और उन्हें सत्ता के गलियारे की फिसलन का बखूबी अंदाजा था। उन्हें पता था कि जो दिया जा रहा है आपको वह लेना होगा, अधूरी संभावनाओं की लालसा में वक्त बरबाद करने का कोई अर्थ नहीं।

धैर्य का प्रतिफल मिला। भले ही वह देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए लेकिन देश के राष्ट्रपति बने और अब भारत रत्न भी। मुखर्जी अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस को क्य सलाह देते? इस सवाल का जवाब देना आसान है और इसका नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की उनकी यात्रा से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से कहा होता कि वह ऊहापोह छोड़े और इस राष्ट्रीय महत्त्व के मसले पर सरकार का साथ दे। कमोबेश उसी तरह जैसे 2009 में वह मिलने आए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के समूह से निपटे थे।

संप्रग सरकार वाम धड़े के चरमपंथियों के खिलाफ बंगाल के जंगलमहल इलाके में व्यापक अभियान छेड़े हुए थी। उस वक्त संप्रग सरकार का समर्थन कर रही तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार इससे परेशान थी। ममता बनर्जी ने अपने सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने भेजा ताकि वे तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम से बात करें और इन अभियानों को रोका जाए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद कबीर सुमन ने किया था। उन्हें बंगाल में बॉब डिलन के समकक्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों का हिमायती माना जाता है।

इस समूह ने मुखर्जी से बात की। दादा, क्या आप गृहमंत्री से कहेंगे कि वह राज्य का यह आतंक बंद करें। सुमन ने समूह की राय से अवगत कराते हुए कहा कि यह सब स्वीकार्य नहीं है जिसने भी ऐसा करने की सलाह दी है वह गलत है।

मुखर्जी ने ऊपर देखा और नरमी से कहा, 'खटमल हैं वे। हम उन्हें कुचल-कुचल कर मारेंगे।' इतना कहकर वह अपने काम पर लग गए। प्रतिनिधिमंडल लौट गया और सुमन दोबारा कभी मुखर्जी से मिलने नहीं गए।

यकीनन मुखर्जी में ऐसा काफी कुछ है जो उन्हें भाजपा के लिहाज से आदर्श बनाता है लेकिन यह वैश्विक नजरिया जिसमें माना जाता है कि भारत अविभाज्य है इसलिए यहां राष्ट्रीयता या आत्मनिर्धारण का कोई मुद्दा ही नहीं है, यही दृष्टिकोण भाजपा को मोदी के करीब लाया। विडंबना देखिए कि मुखर्जी को खुद यह दृष्टि इंदिरा गांधी से मिली।

भारत रत्न से सम्मानित मुखर्जी ने बतौर राष्ट्रपति तमाम दया याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उन्होंने 2016 में बीमा अध्यादेश को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री को तलब किया था। राजग सरकार उसे अपने सुधारात्मक कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। कुछ महीने बाद उन्होंने भूमि अधिग्रहण विधेयक की बारीकियों को लेकर भी सरकार से चर्चा की। जब सरकार ने विवादास्पद शत्रु संपदा अध्यादेश उनके पास भेजा तो उन्होंने अपनी कानून की जानकार टीम को तलब किया और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। यह सारा काम पूरी सहृदयता से किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह तकरीबन हर सप्ताह उनसे मुलाकात करने जाते और उनकी पत्नी के निधन पर वह लगभग पूरा दिन उनके साथ बैठे रहे। मुखर्जी को भारत रत्न इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने किसी तरह का समझौता किया। उन्हें यह इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने प्राप्त हुए अवसरों का लाभ उठाया और इस दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं से कभी समझौता भी नहीं किया। इसमें कहीं न कहीं एक सबक छिपा हुआ है।

कानाफूसी

उलझन की वजह?

भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुनने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया, लेकिन उपाध्यक्ष को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नई लोकसभा का पहला सत्र समाप्त हो चुका है लेकिन भाजपा किसी क्षेत्रीय दल को इस पद के लिए अपना सांसद देने के लिए मना नहीं पाई है। पिछली लोकसभा में सदन गठित होने के 34 दिन के भीतर अन्नाद्रमुक के तंबी दुरई को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। भाजपा ने बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से इस सिलसिले में संपर्क किया लेकिन उनका नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बीजद नेतृत्व नहीं चाहता कि उसके नेता भर्तृहरि महताब इस पद को संभालें जबकि वाईएसआर कांग्रेस भाजपा के करीब नहीं दिखना चाहती है क्योंकि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया।

मंदिर प्रबंधन संस्थान

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार राजधानी भोपाल में एक मंदिर प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित संस्थान में पुजारियों को मंदिरों और मठों के प्रबंधन के बेहतर तौर तरीके सिखाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस संस्थान में छह शाखाएं होंगी जिनमें इंजीनियरिंग, वास्तु, वित्त और इतिहास आदि विषयों के साथ-साथ मंदिरों का प्रबंधन, पूजा अर्चना के तौर तरीके और मंदिरों तथा पुजारियों की सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया जाएगा। सरकार इस संस्थान का बुनियादी ढांचा स्थापित करने पर 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने जा रही है।

आपका पक्ष

आर्थिक तेजी में सभी की भूमिका महत्त्वपूर्ण

वर्तमान भारतीय आर्थिक परिदृश्य में मंदी के संकेत मिलने लगे हैं। इसका साक्ष्य रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी करने से मिलता है। इसके अलावा बैंक ने नीतिगत दरों में 35 आधार अंकों की कटौती की है। रिजर्व बैंक का यह प्रयास बाजार में मौजूद तरलता को बढ़ाने के लिए है जिससे निवेश बढ़े और तेज आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। अमेरिका-चीन की संरक्षणवादी नीति के कारण भी मंदी को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है जो पूरे विश्व को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है। केवल दरों में कटौती करके देश तेज आर्थिक विकास दर हासिल नहीं कर सकेगा। भारत को 2024 तक 5 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने में इस तरह की समस्या बाधक साबित हो सकती है। तेज आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के सभी साझेदारों को अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करना होगा। अर्थव्यवस्था प्रबंधक के सामने मुद्रास्फीति दर को 4

तेज आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के सभी साझेदारों को अपनी भूमिका निभानी होगी

फीसदी से नीचे रखते हुए समेकित मांग को बढ़ावा देकर तथा निजी निवेश में वृद्धि के माध्यम से तेज आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। देश के सभी आर्थिक साझेदारों में रिजर्व बैंक के साथ सरकार भी महत्त्वपूर्ण साझेदार है। सरकार को निवेश अनुकूल माहौल के लिए राजकोषीय प्रबंधन की नीतियों में व्यापार और विनिमय पर पहल तथा निवेशकों के लिए बाधारहित माहौल उपलब्ध कराना प्रमुख कदम है।

सुमित कुमार, सीतामढ़ी

अब कब्जे वाले कश्मीर की बारी

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान को हटाए जाने और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध कर रहा है। पकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति जताई तो वहां से उसे दो टूक जवाब मिला कि यह भारत का आंतरिक मामला है। भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तथा लद्दाख के अक्साई चिन को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह घोषणा करनी चाहिए कि भारत की जमीन पर कब्जा करने वाले देश फौरन इसे खाली करें। इससे भारत को अन्य देशों की मदद मिल सकती है तथा कब्जा करने वाले देशों पर दबाव बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से केंद्र सरकार को पूरी शक्ति मिली है कि वह अपनी जमीन पर से कब्जा हटा सके। भारत को पहले कब्जा करने वाले देशों को चेतावनी देनी चाहिए फिर सेना की मदद से कब्जा हटाना चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।